

भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राचीन काल एवं वर्तमान में रोजगार क्षेत्र का विकास : एक तुलनात्मक अध्ययन

✍ संजीत कुमार राम

शोध सार-

भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के क्षेत्र में 21वीं शदी में मुख्यतः दो दशकों में कायापलट हो गया है, जो देश के नाटकीय आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है। पुरातन काल के कृषि आधार से लेकर आज के तकनीक-संचालित परिदृश्य तक, रोजगार की तलाश ने कई अलग-अलग चरण देखे हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र इसी गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ पर आधारित है। जिसमें भारत में प्राचीन काल और वर्तमान समय के रोजगार की स्थिति, अतीत की सम्भावनाएँ एवं वर्तमान की स्थिति पर एक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द- रोजगार, रोजगार सम्भावनाएँ, रोजगार की स्थिति, तकनीकी संचालित रोजगार परिदृश्य।

शोध-पत्र-

प्राचीन समय में रोजगार मनुष्य की सबसे बुनियादी जरूरतों के कारण अस्तित्व में आई। डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के बावजूद आज भी कई प्राचीन नौकरियाँ मौजूद हैं। जैसे कि शुरुआत से ही शिक्षण को न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर में एक महान पेशा माना जाता था। राजा-महाराजाओं के दरबार में लेखक, लेखाकार, डाक्टर, कलाकार, अधिकारी आदि उच्च पदों पर आसीन होते थे। आर्किटेक्ट और बिल्डरों की बहुत माँग थी, जिसका विवरण भारत में कृषि का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के युग से मिलता है, जहाँ खनिक, बढ़ई, ईंट बनाने वाले, शिकारी, कसाई, वैद्य, चिकित्सक आदि रोजगार के प्रकार थे।

व्यवसायों के पारंपरिक तरीके के पीछे के सिद्धांत-प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में, काम का विभाजन कुछ वास्तविकताओं, सिद्धांतों और जीवन के तरीके पर आधारित था- जैसे-

वर्ण, धर्म और कर्म का सिद्धांत- 'वर्ण, कर्म और धर्म' के सिद्धांतों ने भारत के रोजगार पैटर्न को निर्देशित किया।

'वर्ण' के सिद्धांत ने विभिन्न सामाजिक समूहों को उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति और गुणों के अनुसार कर्तव्य सौंपे थे। इसने व्यवसायों का भागों विभाजन किया और उन्हें करने वालों- ब्राह्मणों को सीखने, अनुसंधान और विकास का काम सौंपा गया। कर्म-प्रधान क्षत्रियों को समाज की रक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का काम दिया गया; वैश्यों को, व्यापार और वाणिज्य का; और शूद्रों को सभी प्रकार की सेवाएँ प्रदान की गईं। वर्ण के सिद्धांत ने लोगों की प्राकृतिक प्रवृत्ति और गुणों के अनुसार

विभिन्न समूहों को कर्तव्य सौंपे थे।

‘धर्म’ और ‘कर्म’ के सिद्धांतों ने विभिन्न व्यवसायों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक समूह के अधिकारों और कर्तव्यों/जिम्मेदारियों की स्पष्ट दृष्टि विकसित की। यह प्रणाली अपने सदस्यों की दैनिक आवश्यकताओं और दिन-प्रतिदिन के संबंधों को अच्छी तरह से प्रबंधित करती थी। इससे लोगों का मनोबल बढ़ा और सामाजिक संतुलन और एकजुटता को बढ़ावा मिला। ‘कर्म’ के सिद्धांत ने कार्य संस्कृति का निर्माण किया। इससे कर्तव्य पर बल पड़ा।

भारत में आक्रमणकारियों के आगमन से पूर्व तक यह व्यवस्था संचालित थी, और यहीं उस समय भारत की समृद्धि का कारण भी थी, किन्तु कालान्तर में इस व्यवस्था को विदेशी आक्रान्ताओं ने बदलने का सफल प्रयास किया। फलस्वरूप वह संस्कृति जो स्वतः रोजगार के स्रोतों की जननी थी, कामकार के पश्चिमी सिद्धान्तों की गुलाम होती गयी।

कम्पनी के शासनकाल में तो भारत में रोजगार के गुणों के लिए विदेशी प्रशिक्षकों की आवश्यकता महसूस होने लगी। कामगारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने लगे और बिना प्रशिक्षण के मज़दूरों को कम मज़दूरी प्रदान किया जाने लगा।

यही कारण था कि स्वतंत्रता-पूर्व भारत में कृषि का प्रभुत्व रहा, जिसमें अधिकांश कार्यबल कार्यरत था। हालाँकि, उपनिवेशवाद के बाद के युग में औद्योगीकरण पर जोर देखा गया, जिससे विनिर्माण नौकरियों की ओर धीरे-धीरे बदलाव आया। यह प्रवृत्ति 20वीं सदी के मध्य तक जारी रही।

1991 में आर्थिक उदारीकरण के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए अपने दरवाजे खोले, जिससे सेवा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिला। प्रौद्योगिकी (I.T.), वित्त और स्वास्थ्य सेवा को शामिल करते हुए यह क्षेत्र एक प्रमुख रोजगार सृजक बन गया। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, सेवा क्षेत्र अब भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 52 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है और कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रोजगार देता है।¹

21वीं सदी में तकनीकी क्रांति की शुरुआत हुई। भारत एक वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में उभरा, जिससे सॉफ्टवेयर विकास, डेटा विज्ञान और साइबर सुरक्षा में कुशल पेशेवरों की भारी मांग पैदा हुई। यह प्रवृत्ति आज भी जारी है, हाल के नैसकॉम डेटा से पता चला है कि भारतीय IT-BPM उद्योग ने वित्त वर्ष 2022-23 में 4.5 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार दिया है।

प्रौद्योगिकी के आगमन, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में, ने भारतीय रोजगार बाजार में क्रांति ला दी है। जहाँ इसने सूचना प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा किए हैं, वहीं इससे पारंपरिक नौकरियों का विस्थापन भी हुआ है। हाल के आँकड़ों के अनुसार, 2030 (विश्व बैंक) तक स्वचालन के कारण भारत के कुल कार्यबल का लगभग 9 प्रतिशत नौकरी विस्थापन के खतरे में है।²

कोविड-19 महामारी ने निस्संदेह नौकरी बाज़ार को बाधित किया। लॉकडाउन और आर्थिक मंदी के कारण नौकरियाँ चली गईं, खासकर आतिथ्य और खुदरा जैसे क्षेत्रों में। हालाँकि, संकट ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में भी तेजी ला दी, जिससे ई-कॉमर्स और दूरस्थ कार्य जैसे क्षेत्रों में विकास को गति मिली।

आज की स्थिति के अनुसार, भारत का रोजगार बाज़ार एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करता है। हालाँकि विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्तियों में पुनरुत्थान हो रहा है, लेकिन सृजित नौकरियों की गुणवत्ता को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं। नियमित वेतनभोगी पदों में स्थिर वृद्धि के साथ, अनौपचारिक काम और स्व-रोजगार में वृद्धि हुई है।¹ 'इंडिया फोरम' द्वारा प्रकाशित की गयी रिपोर्ट 1990 के दशक के मध्य से रोजगार सृजन के तीन चरणों पर प्रकाश डालता है, जो अनौपचारिक साधनों के माध्यम से नौकरियों की 'मात्र' बढ़ाने की हालिया प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है। इस रिपोर्ट में भविष्य के रोजगार के रूझान पर अवलोकन प्रस्तुत करते हुए यह सम्भावना व्यक्त की गयी है कि स्वचालन प्रभाव के द्वारा कुछ क्षेत्रों में नौकरियों को विस्थापित करना जारी रखेगा जबकि अन्य में नए अवसर पैदा करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स में कौशल की माँग अधिक रहने की उम्मीद है।

गिग (GIG) अर्थव्यवस्था का उदय भारत में विकसित हो रहे नौकरी बाज़ार की एक प्रमुख विशेषता रही है। फ्रीलांस काम (Freelance Work) और अल्पकालिक अनुबंधों (Short-term Contracts) की पेशकश करने वाले प्लेटफार्मों ने लोकप्रियता हासिल की है, खासकर युवा पीढ़ी के बीच। हाल के आँकड़ों से पता चलता है कि 15 मिलियन से अधिक भारतीय ग्राफिक डिजाइन से लेकर सामग्री लेखन तक विभिन्न क्षेत्रों में फ्रीलांस काम (Freelance Work) में लगे हुए हैं।⁴

आज नियोक्ता (Employers) योग्यता (Qualifications) से अधिक कौशल (Skills) को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे नियुक्ति प्रथाओं में बदलाव आ रहा है। डेटा विश्लेषण, डिजिटल मार्केटिंग और कोडिंग जैसे कौशल उच्च माँग में हैं, जिससे प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले पेशेवरों के लिए वेतन बढ़ रहा है। हालाँकि, नौकरी चाहने वालों के पास मौजूद कौशल और नियोक्ताओं (Employers) के लिए आवश्यक कौशल के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है, जो अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पहल की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

भारत का रोजगार बाज़ार उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव और तकनीकी प्रगति के कारण नए क्षेत्रों के उद्भव का गवाह बन रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स और एड-टेक जैसे उद्योग तेजी से विकास का अनुभव कर रहे हैं और रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं।

भारत सरकार ने उभरते रोजगार बाज़ार में चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए कई पहल शुरू की हैं। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य कार्यबल के बीच कौशल विकास, उद्यमिता और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। विश्व बैंक की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में युवा आबादी है, जिसमें 65 प्रतिशत से अधिक कामकाजी आयु वर्ग (15-64 वर्ष) के अंतर्गत आते हैं। यह जनसांख्यिकीय लाभांश आर्थिक विकास के लिए एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करता है। हालाँकि, इस कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से में उभरते नौकरी बाज़ार द्वारा मांगे जाने वाले आवश्यक कौशल का अभाव है। अपनी स्थापना (जुलाई 2015) के बाद से, स्किल इंडिया ने लाखों व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है। MSDE की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, 88 मिलियन से अधिक लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) स्किल इंडिया का नेतृत्व करता है। यह कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के लिए उद्योग निकायों, प्रशिक्षण प्रदाताओं और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है। स्किल इंडिया में आईटी, विनिर्माण, निर्माण,

ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षण उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) कौशल मानकों को स्थापित करने और प्रमाणपत्र जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पूरे भारत में एक समान प्रणाली सुनिश्चित करता है। डिजिटल साक्षरता के बढ़ते महत्व को पहचानते हुए, स्किल इंडिया ने ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने के लिए 'स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म' जैसी पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य इच्छुक व्यवसाय मालिकों को ऊष्मायन सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करके एक उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना भी है।

हालाँकि, चुनौतियाँ बनी हुई हैं। प्रदान किए गए प्रशिक्षण और उद्योग की अपेक्षाओं के बीच अंतर को पाटने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, सभी प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। भारत में कार्यस्थल में लैंगिक विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों ने गति पकड़ ली है। कंपनियाँ तेजी से समावेशी नीतियाँ बनाने और पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। हालाँकि, लैंगिक असमानताएँ बनी रहती हैं, विशेष रूप से नेतृत्व भूमिकाओं और पुरुष-प्रधान उद्योगों में, जो अंतर को पाटने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

भारतीय सरकार ने 'नमो ड्रोन दीदियों' योजना को प्रारम्भ किया है। यह पहल ग्रामीण भारत में महिला उद्यमियों को कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन संचालित करने के लिए प्रशिक्षण और संसाधनों से लैस करके सशक्त बनाती है। ड्रोन प्रदर्शन सशक्त नारी-विकसित भारत कार्यक्रम का हिस्सा थे, जो महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित एक सरकारी पहल है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 1,000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी वितरित किए। कृषि क्षेत्र में अधिक महिला उद्यमियों को सक्षम और सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर शुरू करना एक स्वागत योग्य कदम है।

कृषि ड्रोन कई लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें सटीक छिड़काव भी शामिल है: ड्रोन पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक सटीकता और दक्षता के साथ उर्वरक, कीटनाशकों और जड़ी-बूटियों को लागू कर सकते हैं, बर्बादी और पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकते हैं। मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरों से लैस ड्रोन किसानों को फसल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जल्द पहचान करने में मदद कर सकते हैं, जिससे समय पर हस्तक्षेप की अनुमति मिलती है। ड्रोन फसल छिड़काव जैसे कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं, संभावित रूप से श्रम आवश्यकताओं और संबंधित लागतों को कम कर सकते हैं। इस तकनीक से महिलाओं को सशक्त बनाकर, कार्यक्रम न केवल कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दे सकता है बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए नए आर्थिक अवसर भी पैदा कर सकता है।

ध्यान देने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। अक्टूबर 2023 तक, देश के 763 जिलों में इन्वेस्ट इंडिया, के तहत फैले 1.12 मिलियन से अधिक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। यह दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो देश के भीतर अपार क्षमता और उद्यमशीलता की शक्ति को प्रदर्शित करता है।

भारतीय स्टार्टअप परिदृश्य साल-दर-साल अभूतपूर्व वृद्धि का अनुभव कर रहा है। जबकि कुल

स्टार्टअप की सटीक संख्या स्रोत के आधार पर भिन्न होती है, स्टेटिस्टा ने फरवरी 2023 तक 92,000 से अधिक स्टार्टअप की रिपोर्ट दी है। यह एक युवा, तकनीक-प्रेमी आबादी और सक्रिय रूप से उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाली सरकार द्वारा संचालित लगातार विकास पथ को इंगित करता है। फिनटेक सबसे अधिक फंडिंग सौदों को आकर्षित करते हुए सबसे लोकप्रिय क्षेत्र के रूप में उभरा है। अकेले 2022 की पहली छमाही में, स्टार्टअप्स ने 17 अरब डॉलर की जबरदस्त फंडिंग हासिल की, जो पिछले वर्ष इन्वेस्ट इंडिया, से उल्लेखनीय वृद्धि है। निवेशकों का यह मजबूत विश्वास नवाचार को बढ़ावा देता है और नए यूनिकॉर्न- 1 अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाली निजी कंपनियों के उद्भव का मार्ग प्रशस्त करता है।

भारतीय स्टार्टअप परिदृश्य यूनिकॉर्न के ग्लैमर से कहीं आगे तक फैला हुआ है। स्टार्टअप आईटी सेवाओं और स्वास्थ्य सेवा से लेकर शिक्षा और कृषि इन्वेस्ट इंडिया, तक 56 विविध क्षेत्रों में चुनौतियों से निपट रहे हैं और समाधान तैयार कर रहे हैं। यह व्यापक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि विशाल और विविध आबादी की जरूरतों को पूरा करते हुए नवाचार देश के सभी कोनों तक पहुँचे।⁵

2016 में लॉन्च किया गया, स्टार्टअप इंडिया पहल सरकारी समर्थन की आधारशिला के रूप में खड़ा है। यह महत्वाकांक्षी संस्थापकों के लिए एक व्यापक टूलकिट प्रदान करता है। प्रारंभिक वित्तीय बाधाओं को पहचानते हुए, सरकार महत्वपूर्ण प्रारंभिक वर्षों में कर छूट प्रदान करती है, जिससे स्टार्टअप को पूंजी को विकास में पुनः निवेश करने की अनुमति मिलती है।⁶ इन्वेस्ट इंडिया की रिपोर्ट का यह भी मानना है कि नौकरशाही स्टार्टअप योजना के लिए हानिकारक भूमिका में है। स्टार्टअप इंडिया अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और स्व-प्रमाणन विकल्प प्रदान करता है, जिससे संचालन का मार्ग सरल हो जाता है। बौद्धिक संपदा की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। यह पहल पेटेंट आवेदनों में तेजी लाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्टार्टअप अपने नवाचारों का स्वामित्व शीघ्रता से सुरक्षित कर सकें। सिडबी फंड ऑफ फंड्स उन उद्यम पूंजीपतियों के लिए संसाधनों का उपयोग करता है जो आशाजनक स्टार्टअप में निवेश करते हैं, और बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।⁷

सरकार की प्रतिबद्धता स्टार्टअप इंडिया से भी आगे तक फैली हुई है। 2016 में स्थापित अटल इनोवेशन मिशन (AIM) नवाचार की राष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ावा देता है। यह अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (AIC) के माध्यम से स्टार्टअप का समर्थन करता है। अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (AIC) वे भौतिक इकाई है जो शुरुआती चरण के स्टार्टअप को इन्क्यूबेशन सुविधाएँ, सलाह और फंडिंग प्रदान करते हैं, एक पोषण लॉन्चपैड प्रदान करते हैं। अनुदान और लक्षित पहल महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार स्थापित अटल इनोवेशन मिशन (AIM) रोजगार हेतु शीघ्र प्रदर्शन के महत्त्व को समझता है। इसी प्रकार स्कूलों में टिकरिंग लेब्स युवा दिमागों में वैज्ञानिक जिज्ञासा और नवीनता जगाती है, जिससे उद्यमियों की अगली पीढ़ी का विकास होता है। विभिन्न सरकारी मंत्रालय क्षेत्र-विशिष्ट सहायता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण प्रदान करती है, जिनमें से कई स्टार्टअप के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI)⁸ आईटी और आईटी-सक्षम स्टार्टअप के लिए बुनियादी ढांचा और प्रोत्साहन प्रदान करता है। सरकार ने सार्वजनिक खरीद के मानदंडों में भी ढील दी है, जिससे स्टार्टअप्स को सरकारी अनुबंधों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिल गई है, जिससे मूल्यवान बाज़ार

तक पहुंच खुल गई है। सरकारी पहल भारत के नौकरी बाज़ार के विकास को आगे बढ़ाती है, जो व्यापक आर्थिक और सामाजिक बदलावों को प्रतिबिंबित करती है।⁹

निष्कर्ष-

भारत में वर्तमान रोजगार के अवसरों के उक्त अध्ययन के आलोक में यह कहा जा सकता है कि भले भारत में रोजगार के इतिहास कृषि के परम्परागत स्वरूप का रहा हो। फिर भी सदियों तक कृषि के माध्यम से ही वह विश्व में अग्रणी रहा है और आज जब विश्व में रोजगार के नये परिभाषाएँ रची जा रही हैं, तो भी भारतीय अर्थव्यवस्था उसके लिए सम्यक सामर्थ्य रखती है। जो वर्तमान सम्भावनाओं के आधार पर 21वीं शताब्दी में सबसे बड़ी जनसंख्या का आभरण करते हुए यह सामर्थ्य रखती है कि नये रोजगार अवसरों के अनुसार रोजगार अवसरों का सृजन ही नहीं बल्कि गुणवत्ता परक रोजगार सम्भावनों से ओत-प्रोत भी है।

शोध संदर्भ-

1. <https://www.aajtak.in/topic/economic-survey>
2. <https://aim.gov.in/>
3. <https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS>
4. <https://www.iari.res.in/en/research.php>
5. <https://www.msde.gov.in/en/reports-documents/annual-reports>
6. <https://stpi.in/>
7. <https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/startup-scheme.html>
8. <https://www.theindiaforum.in/>

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. विश्व बैंक रिपोर्ट।
2. तथैव।
3. 'इंडिया फोरम : मात्र बनाम गुणवत्ता : भारतीय श्रम बाजार में नौकरी निर्माण में दीर्घकालिक रुझान'।
4. <https://www.aajtak.in/topic/economic-survey>
5. <https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/startup-scheme.html>
6. इन्वेस्ट इंडिया
7. <https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/startup-scheme.html>
8. <https://stpi.in/>
9. <https://aim.gov.in/>

